



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229729
CG-DL-E-16092021-229729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943

No. 272]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर-19/2021)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पॉलीटेट्राफ्लूओरोएथिलीन” (पीटीएफई) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा सं 7/4/2021-डीजीटीआर.—

1. मै. गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमि. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

“पालीटेड्राफ्लूओरोएथिलीन” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या विशेष रूप से “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के बाद भी संबद्ध देश से पाटन जारी है और यह कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति और पाटन के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्कों के विस्तार के लिए आवेदक ने अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 14/25/2003-डीजीएडी, दिनांक 27 जुलाई, 2004 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में आरंभ की गई थी। विस्तृत जांच के पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/25/2003-डीजीएडी, दिनांक 25 जुलाई, 2005 के अनुसार चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की थी। प्राधिकारी की सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 91/2005-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। तदनुसार, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 15/33/2008-डीजीएडी दिनांक 27 फरवरी, 2009 के अनुसार आरंभ की गई थी और पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप को दिनांक 26 फरवरी, 2010 को जारी अंतिम जांच परिणाम के अनुसार परिशोधित किया गया था। प्राधिकारी की सिफारिश को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 42/2010 दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था। इस प्रकार संशोधित और लागू शुल्कों को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 81/2011-सीमाशुल्क दिनांक 24 अगस्त, 2011 के अनुसार प्रथम निर्णायक समीक्षा के अनुसार जारी रखा गया। तत्पश्चात, द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच को अधिसूचना सं. 15/11/2016-डीजीएडी दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार आरंभ किया गया था और 23 जून, 2017 को जारी अंतिम जांच परिणाम के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों को विस्तारित किया गया था और अधिसूचना सं. 36/2017-सी. शु. (एडीडी) दिनांक 28 जुलाई, 2017 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 27 जुलाई, 2022 तक लागू है।
4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. एडीडी-एसी- 03/2020 दिनांक 27 जनवरी के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच समाप्त की और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संसाधित पी टी एफ ई संघटकों के आयातों पर शुल्क लागू किए। अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा चीन से संसाधित पी टी एफ ई संघटकों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिए गए। उपर्युक्त शुल्क चीन जन.गण. से पी टी एफ ई पर लगाए गए शुल्क की अवधि तक है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “पालीटेड्राफ्लूओरोएथिलीन” (पीटीएफई) है। यह अंतिम जांच परिणाम सं. 15/11/2016-डीजीएडी दिनांक 23 जून, 2017 के अनुसार, पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार ही है।

“वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पालीटेट्राफ्लूओरोएथिलीन” (पीटीएफई) है (जिसे यहां संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)। संबद्ध वस्तु को सामंजस्य प्रणाली के आधार पर भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आई टी सी) में उप शीर्ष सं. 390461 पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत उप शीर्ष सं. 39046100 पर और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। पी टी एफ ई को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जैसे मोल्लिंग ग्रेड, फाइन पाउडर, एक्जूस डिस-परसन कंपाउंड ग्रेड्स और फिल्ड ग्रेड। सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर हैं। पी टी एफ ई का प्रयोग मुख्य रूप से उनकी अद्वितीय विशेषताओं जिनमें रासायनिक जड़ता, इलैक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, घर्षण का कम गुणांक, गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, रेडिएशन के प्रति विरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण का निम्न स्तर और व्यापक आवृत्ति रेंज पर उत्कृष्ट विद्युत गुण शामिल हैं, के लिए इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और केमिकल उद्योगों में किया जाता है।”

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा और इस अवधि के दौरान कोई खास विकास नहीं हुआ है। हालांकि आवेदकों ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बीच उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। आवेदकों ने पीसीएन को PTFE, PT-PTFE, D-PTFE, A-PTFE, C-PTFE के रूप में प्रस्तावित किया है। तथापि, इच्छुक पक्ष इस जांच के शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजन के लिए पीसीएन को अंतिम रूप देने के लिए अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान कर सकते हैं।
7. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग इसकी अद्वितीय विशेषताओं जैसे रासायनिक जड़ता, घर्षण का कम गुणांक, स्थिर और गतिशील घर्षण का निम्न प्रदर्शन, गैर-विषैले, गैर-ज्वलनशील और व्यापक आवृत्ति रेंज पर उत्कृष्ट विद्युत गुण, रेडिएशन के प्रति विरोध और ऑपरेटिंग टेंपरेचर रेंज शामिल हैं, के कारण मुख्य रूप से इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 3904.6100 के तहत अध्याय 39 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे में किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
समान वस्तु
9. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं से तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अनुसार इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

10. यह आवेदन मै गुजरात .फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटेड के द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा पीओआई के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में “प्रमुख समानुपात” के लिए उत्तरदायी है। इसे ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के पश्चात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(घ) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन ऊपर नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों के मानदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
13. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी जानकारी के अभाव में इसके संबंध में विश्वसनीय सूचना नहीं मिल पाई थी। प्राधिकारी ने एडी नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नोट किया कि जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से भारत में आयात गैर-पाटित आयातों में सबसे अधिक है और इसलिए ये प्रथम दृष्टया भारत में देय मूल्य को स्थापित करते हैं और दीक्षा के प्रयोजन के लिए सांकेतिक NV के रूप में अपनाया गया।
14. जांच शुरुआत के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा सुझाए गए सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए क्रिया पद्धति पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

15. संबद्ध देश संबद्ध वस्तुओं के लिए से निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के उपलब्ध सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रभार, कमीशन, संभाल प्रभार तथा बैंक प्रभार के लिए सीआईएफ निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है, जिससे यह इंगित होता है कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का निर्यातित किया जाना जारी है।

क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना

17. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और घटती कीमत, निर्यातकों द्वारा अपनाए गए प्रवंचनात्मक अभ्यास, सकारात्मक पाटन मार्जिन, संबद्ध देश में अप्रयुक्त महत्वपूर्ण क्षमताओं और भारतीय बाजार में कीमत आकर्षकता पर विचार करते हुए, शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्रथम दृष्टया यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

20. प्राधिकारी ने जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 (12 माह) की अवधि का प्रस्ताव किया है। क्षति की अवधि में तीन पूर्ववर्ती वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

21. निर्णायक समीक्षा जांच के पाटन और क्षति की संभावना संबंधी विश्लेषण को अपनाया जाएगा।
22. इस समीक्षा जांच में जिसमें अधिसूचना सं. 14/25/2003-डीजीएडी दिनांक 25 जुलाई, 2005, अधिसूचना सं. 15/33/2008-डी जी ए डी, दिनांक 26 फरवरी, 2010 और अधिसूचना सं. 15/11/2016-डी जी ए डी दिनांक 23 जून, 2017 जिनमें चीन जन.गण. से “पालीटेट्राफ्लूओरोएथिलीन (पीटीएफई)” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

23. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

24. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in; dir13-dgtr@gov.in; dir11-dgtr@gov.in; और dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
25. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in; dir13-dgtr@gov.in; dir11-dgtr@gov.in; और dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिसों के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी

साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
33. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
35. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
36. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
37. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
38. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

[Case No. AD (SSR) 19/2021]

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene (PTFE)” originating in or exported from China PR.

No.7/4/2021-DGTR.—

1. M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter referred to as the ‘Applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene (PTFE)” (hereinafter referred to as ‘product under consideration’ or ‘PUC’ or ‘subject goods’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Applicant has alleged that dumping from the subject country has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of cessation of duties. The Applicant has requested for extension of duties on imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority vide Notification No. 14/25/2003-DGAD, dated 27th July 2004. After a detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of Anti-dumping duties on

imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 14/25/2003-DGAD, dated 25th July 2005. The recommendation of the Authority was implemented by the Ministry of Finance vide Custom Notification No. 91/2005-Customs (ADD) dated 17th October, 2005. Subsequently, a Mid-Term review of the said definitive antidumping duty was initiated by the Authority vide Notification No. 15/33/2008-DGAD, dated 27th February 2009 and the form of anti-dumping duty was modified vide the final findings issued dated 26th February 2010. The recommendation of the Authority was implemented by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 42/2010 dated 05th April 2010. The duties so revised and imposed were continued pursuant to first Sunset review vide Customs Notification No. 81/2011-Customs dated 24th August 2011. Thereafter, second Sunset review investigation was initiated vide Notification No. 15/11/2016-DGAD, dated 08th July 2016 and anti-dumping duties were extended vide final findings issued on 23rd June 2017, and imposed by Ministry of Finance vide Notification No. 36/2017-Customs (ADD), dated 28th July 2017. The current anti-dumping duty are in force till 27th July 2022.

4. The Designated Authority concluded anti-circumvention investigation vide Final Findings No. ADD-AC-03/2020, dated 27th January 2021 and extended duties on imports of processed PTFE components originating in or exported from China PR. Antidumping duties were extended on processed PTFE components from China by the Ministry of Finance vide Notification No. 25/2021-Customs (ADD) dated 26th April 2021. The said duty is co terminus with the duty levied on PTFE from China PR.

Produce Under Consideration

5. The product under consideration in the present investigation is “Polytetrafluoroethylene (PTFE)”, this is same as same as defined by the Authority in the previous sunset review investigation, vide Final Findings No. 15/11/2016-DGAD dated 23rd June 2017.

The product under consideration in the present case is "Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from China PR" (also referred to as subject goods hereinafter). The subject goods are classified under subheading no 390461 under Customs tariff Act and at subheading no. 39046100 in the Indian Trade Classification (ITC) based on Harmonized System. Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations. PTFE is produced in various grades like moulding grade, fine powder, aqueous dispersions compound grades and filled grades. All grades are within the scope of the product under consideration. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, non-toxic, nonflammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.”

6. The present investigation being a Sunset Review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original investigation, and no significant developments have taken place over the period. However, the Applicants have proposed for the adoption of Product Control Numbers (PCNs) for the fair comparison between different types of products. The Applicants have proposed the PCNs as PTFE, PT-PTFE, D-PTFE, A-PTFE, C-PTFE. The interested parties however, can provide their comments/suggestions for the finalization of PCNs for the purpose of this investigation within 15 days from the date of initiation of this investigation.

7. The subject goods are primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries because of its certain unique characteristics such as Chemical Inertness; Low coefficient of friction; Exhibits lowest value of static and dynamic friction; Non- toxic; Non- flammable; Outstanding electrical properties over a wide frequency range; Resistance to radiation; and Operating temperature range.
8. The product under consideration is classified under the Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975, under the customs sub-heading 3904.6100. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the investigation.

Like article

9. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry and Standing

10. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Limited. The applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the Product under Consideration in India.
11. As per evidence available on record, the production of the applicant account for "a major proportion" in the domestic production of the like article. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of alleged dumping

Normal Value for China PR

12. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese Producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
13. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the same in absence of any publicly available information. The Authority

keeping in view the provisions under para 7 of Annex-1 of AD Rule notes that imports from EU to India during the Period of Investigation are highest amongst non-dumped imports and therefore these prima facie establishes the price payable in India and have been adopted as indicative NV for the purpose of initiation.

14. For the purpose of initiation, the Authority has considered the methodology for determination of normal value suggested by the applicant.

Export Price

15. The export price for subject goods for the subject country has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, insurance, port expenses, commission, handling charges and bank charges to arrive at the CIF export price.

Dumping Margin

16. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin is above de-minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have continued to be exported at dumped prices, in spite of antidumping duty in force.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury

17. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the volume and declining price of imports of subject goods from subject country, circumvention practice engaged by the exporters, positive dumping margin, significant unutilized capacities in subject country, and price attractiveness of Indian market. It is prima facie noted that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

Subject Country

19. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

20. The Authority proposes the period of investigation (POI) for the present investigation as April 2020 – March 2021 (12 Months). The injury investigation period will cover the three preceding years 2017 – 18, 2018 – 19, 2019 – 20 and the POI.

Procedure

21. The sunset review investigation will undertake likelihood analysis of dumping and Injury.
22. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/25/2003-DGAD, dated 25th July 2005, Notification No. 15/33/2008-DGAD, dated 26th February 2010, and Notification No. 15/11/2016-DGAD, dated 23rd June 2017 recommending imposition of Anti-dumping duty on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' from China PR.
23. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

24. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in; dir13-dgtr@gov.in; dir11-dgtr@gov.in; and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
28. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time-Limit

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dir11-dgtr@gov.in, and dd16-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

31. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to submit simultaneously a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-confidential versions separately.
33. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

39. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority